* 20th Year
* Issue: 117
* 28.08.2026 (FRIDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

राष्ट्रपति मुर्मू ने आईएफएस अधिकारियों को दिया राष्ट्रहित सर्वोपरि का मंत्र, जनसेवा पर जोर

नयी दिल्ली २७/०८ (संवाददाता): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के नवनियुक्त अधिकारियों को 'राष्ट्रहित सर्वोपरि' का मंत्र देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि दुनिया के साथ भारत का जुड़ाव हमेशा देश के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। आईएफएस के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति दुनिया के साथ देश के जुड़ाव के लिए नयी संभावनाएं पैदा कर रही है। उन्होंने राजनयिकों को निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों के प्रति सतर्क रहने तथा ऐसी साझेदारियां विकसित करने की सलाह दी, जो भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाएं। मुर्मू ने कहा कि कूटनीति को भारत की समृद्धि में सीधे योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया के साथ भारत का जुड़ाव हमेशा देश के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए -'राष्ट्रहित सर्वोपरि'।

राष्ट्रपति ने कहा कि यह भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के पेशेवर जीवन का स्थायी सिद्धांत होना चाहिए।राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, मुर्मू ने कहा कि राजनयिकों को अपने संपर्कों को केवल सरकारी कार्यालयों और आधिकारिक बैठकों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें विश्वविद्यालयों, कारोबार जगत, शोधकर्ताओं, नवोन्मेषकों, सांस्कृतिक संस्थानों, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों तक भी पहुंच बनानी चाहिए। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ सार्थक संपर्क कायम करने की सलाह दी, खासकर प्रवासी समुदाय के युवाओं को भारत से जुड़े रहने और देश की विकास यात्रा में योगदान देने के अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

कूटनीति के स्वरूप में तेजी से हो रहे बदलाव का उल्लेख करते हुए मुर्मू ने कहा कि प्रौद्योगिकी देशों के संवाद करने, कारोबार के संचालन और नागरिकों के सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने के तरीके को बदल रही है। उन्होंने कहा कि विदेशों में स्थित भारत के मिशनों को भी इस बदलाव के साथ कदमताल करनी होगी। मुर्मू ने कहा, ''प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बेहतर शासन और गहरे जुड़ाव के साधन के रूप में किया जाना चाहिए, लेकिन इसे कभी भी मानवीय संवेदना का स्थान नहीं लेना चाहिए।'' राष्ट्रपति ने राजनयिकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जरूरत के समय भारतीय मिशन हमेशा देश के नागरिकों के लिए सुलभ और उपलज़्ध रहें।उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर चलाए गए निकासी और मानवीय अभियानों के दौरान प्रदर्शित परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुर्मू ने कहा, ''मदद मांगने वाले प्रत्येक भारतीय को महसूस होना चाहिए कि उनका मिशन सुलभ, संवेदनशील और भरोसेमंद है।'' मुर्मू ने कहा कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी न केवल हजारों वर्षों पुरानी सज़्यता वाले देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि वे एक युवा, गतिशील और आकांक्षी भारत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि शांति, बहुलवाद, संवाद, सह-अस्तित्व और विविधता के प्रति सज़्मान भारत की सज़्यतागत सोच 'वसुधैव कुटुज़्बकम' में गहराई से निहित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से अनिश्चित और जटिल होती दुनिया में राजनयिकों को चुस्त, जिज्ञासु और लगातार सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ''सबसे बढ़कर, उन्हें विनम्रता बनाए रखनी चाहिए।'' मुर्मू ने युवा प्रशिक्षु अधिकारियों से विदेश यात्रा के दौरान हमेशा यह याद रखने का आग्रह किया कि वे केवल भारत सरकार का ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों और उनकी उज़्मीदों तथा आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मुर्मू ने अधिकारियों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पेशेवर आचरण के उच्चतम मानदंड बनाए रखने की सलाह दी।भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों और भूटान के दो राजनयिकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की।

सीजेआई सूर्यकांत बोले, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक सीजे पर लगे आरोपों की जांच केवल संस्थागत तंत्र करेगा

नयी दिल्ली २७/०८ (संवाददाता): भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुज़्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता द्वारा लगाए गए आरोपों पर सार्वजनिक रूप से फैसला नहीं किया जा सकता और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित न्यायाधीश को ''अपना पक्ष रखने का उचित अवसर'' दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता ने प्रधान न्यायाधीश को लिखे अपने तीन पत्रों में न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और उनसे राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य के बाहर से किसी स्थायी मुज़्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति मेहता ने दो, 10 और 17 अगस्त को लिखे अपने तीन पत्रों में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुज़्य न्यायाधीश पर ''कुप्रशासन'', ''कदाचार'', ''भाई-भतीजावाद'' और ''पक्षपात'' के आरोप लगाए हैं। जर्मनी और ब्रिटेन की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए प्रधान

न्यायाधीश सूर्यकांत ने इन पत्रों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने न्यायमूर्ति मेहता द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का पहले ही संज्ञान ले लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा, ''किसी मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों से केवल स्थापित संस्थागत तंत्र के माध्यम से ही निपटा जाना चाहिए।'' देर शाम जारी एक बयान में कहा गया, ''प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पत्रों में कही गई बातों पर सार्वजनिक रूप से फैसला नहीं किया जा सकता और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।'' प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''केवल आरोप लगाए जाने को संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ अपने आप में निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।'' उन्होंने कहा कि मामले की उचित स्तर पर जांच की जा रही है और इस प्रक्रिया में न्यायमूर्ति मेहता द्वारा उपलज़्ध कराई गई सामग्री के साथ-साथ न्यायमूर्ति शर्मा के जवाब पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक मुज़्य न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति शर्मा के बने रहने, उनके तबादले या उनसे संबंधित किसी अन्य प्रशासनिक कार्रवाई पर फैसला सक्षम संस्थागत प्राधिकारी सभी सामग्री पर उचित विचार करने के बाद करेगा।

बयान में कहा गया, ''प्रधान न्यायाधीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों से जुड़ी व्यक्तिगत शिकायतों का फैसला मीडिया में किए जाने वाले परस्पर विरोधी दावों के आधार पर नहीं होने दे सकता।'' प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वह और कॉलेजियम के अन्य सदस्य शेष उच्च न्यायालयों में मुज़्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पहले से काम कर रहे हैं।

संसद के एक और सत्र की हलचल! संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले-सत्रावसान नहीं हुआ, सरकार जब चाहे बुला सकती है बैठक

नयी दिल्ली २७/०८ (संवाददाता): संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद की एक और बैठक बुलाए जाने की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मॉनसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है, केवल अनिश्चित काल के लिए स्थगन हुआ है। ऐसे में तकनीकी और संवैधानिक परंपराओं के तहत सरकार राष्ट्रपति से अनुरोध कर सदन की बैठक दोबारा बुला सकती है। %इंडिया टुडे% को दिए एक साक्षात्कार में विशेष सत्र या अतिरिक्त बैठक से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि संसद का सत्र बुलाना पूरी तरह से सरकार का अधिकार क्षेत्र है। इंडिया टुडे की मैनेजिंग एडिटर प्रीति चौधरी के साथ एक इंटरव्यू में, रिजिजू से पूछा गया कि ज़्या सरकार कोई और बैठक

या विशेष सत्र बुला सकती है। उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन संसदीय परंपराओं की ओर इशारा किया जिनके तहत सदन की बैठक फिर से हो सकती है। उन्होंने कहा, यह सरकार पर निर्भर करता है। जब भी संसद को बुलाना होता है, तो सरकार ही फैसला करती है और राष्ट्रपति से सत्र बुलाने का अनुरोध करती है। जब सदन का सत्रावसान नहीं हुआ होता है, तो सत्र बुलाया जा सकता है।हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि ज़्या इसका मतलब यह है कि कोई विशेष सत्र हो सकता है, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। जब चौधरी ने कहा कि उनकी बातों का मतलब यह निकाला जा सकता है कि एक और बैठक की संभावना खुली है, तो रिजिजू ने जवाब दिया, आप इसे दोनों तरह से समझ सकती हैं। उन्होंने बिना विस्तार से बताए कहा, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर, मैं हमेशा लोगों की जांच-परख और निगरानी के लिए तैयार रहता हूं, और फिर जब समय आएगा... खास तौर पर यह पूछे जाने पर कि ज़्या संसद का कोई और सत्र हो सकता है, रिजिजू ने कहा, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अरुणाचल के सांसद ने अपनी बात को पुज़्ता करने के लिए संसदीय इतिहास का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 1952 के बाद से ऐसे कई मौके आए हैं जब संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित तो किया गया, लेकिन सत्रावसान नहीं किया गया, और उसके बाद सत्र को फिर से बुलाया गया। उन्होंने कहा, इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको सूची दे दूंगा। रिजिजू की ये बातें ऐसे समय में सामने आई हैं जब मॉनसून सत्र को सत्रावसान किए बिना अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद सरकार के अगले कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।

हर्ष दूबे के नेतृत्व जेपी नड्डा से मिल आरक्षण सुधार कार्यकर्ता

नयी दिल्ली २७/०८ (संवाददाता): नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों के हंगामे के कुछ दिनों बाद, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को कोटा-सुधार कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में हृश्वश्वज्ञ की तैयारी कर रहे हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक जैसे कार्यकर्ता शामिल थे, जो भारत के जाति-आधारित आरक्षण ढांचे में बदलाव और सभी समुदायों के लिए समान अवसरों की मांग कर रहे हैं। इस मीटिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दिपके ने पूछा कि नड्डा ने यह ज़्यों नहीं बताया कि जंतर-मंतर पर 21 अगस्त को हुआ विरोध प्रदर्शन किसलिए था। दिपके ने ङ्क पर कहा कि देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में

ज़्या सोचते हैं। ङ्क पर नड्डा ने कहा कि यह दोस्ताना बातचीत पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार हुई थी और कोटा-सुधार कार्यकर्ताओं के साथ जल्द ही एक और बैठक होगी। हालाँकि, उन्होंने न तो आंदोलन का नाम लिया और न ही चर्चा की गई मांगों या प्रतिनिधिमंडल को दिए गए किसी आश्वासन का खुलासा किया।

यह बैठक हर्ष दुबे और आरक्षण-सुधार से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों की लखनऊ में उज़र प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाक़ात के कुछ दिनों बाद हो रही है। पाठक ने उनकी मांगों को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने और 48 घंटे के अंदर किसी केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक का इंतज़ाम करने का वादा किया था। यह बैठक 21 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुई उस भीड़ के बाद हो रही है, जिसमें अनरिज़र्व्ड कैटेगरी% (सामान्य श्रेणी) के हज़ारों लोग शामिल हुए थे। यह भीड़ दुबे और कोटा-सुधार कार्यकर्ताओं जैसे अनुराधा तिवारी और अजीत भारती के नेतृत्व में हफ़्तों तक चले ऑनलाइन अभियान के बाद जुटी थी। प्रदर्शनकारियों ने जाति-आधारित आरक्षण और ाष्ट के इक्विटी नियमों (जिन पर अब रोक लगी हुई है) का विरोध किया। कई लोगों ने मांग की कि सकारात्मक कार्रवाई (अफ़र्मेटिव एज़्शन) के फ़ायदों को आर्थिक स्थितियों से जोड़ा जाए। इस प्रदर्शन में जनरल सेना, चाणज़्य सेना और श्री राजपूत करणी सेना जैसे संगठन भी शामिल हुए; करणी सेना ने राजस्थान के जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन किए हैं। हर्ष दुबे ने इस बातचीत को समाज के सभी वर्गों के हित में एक सकारात्मक पहल बताया।

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने 21 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के बारे में नड्डा के साथ संक्षिप्त चर्चा की और इस बैठक को बातचीत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। दुबे ने लिखा कि हम बहुत जल्द माननीय जेपी नड्डा जी से फिर मिलेंगे और समाज के सभी वर्गों के हित में सकारात्मक और उचित निर्णय के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह आंदोलन किसी खास समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं था।

परिसीमन को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को चेताया, कहा-बिना चर्चा कोई बड़ा फैसला न लें

नयी दिल्ली २७/०८ (संवाददाता): कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को प्रस्तावों की विस्तार से समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। गुरुवार को लिखे अपने पत्र में, खड़गे ने 16 जुलाई, 2026 को की गई अपनी पिछली अपील का ज़िक्र किया, जो इस मामले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की खबरों के बाद की गई थी।

खड़गे ने कहा कि मैंने पिछली बार आपको 16 जुलाई, 2026 को पत्र लिखकर परिसीमन के लिए सरकार के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था

उन्होंने आगे कहा कि मैंने आपसे यह भी अनुरोध किया था कि संसद के किसी भी विशेष सत्र में, जिस पर आप विचार कर रहे हों, इन प्रस्तावों को पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों को इनका विस्तार से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। खड़गे ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का साफ़ रुख़ दोहराया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का रुख़ बिल्कुल साफ़ है। लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संज़्या को अगले 25 सालों तक बनाए रखा जाए। उन्होंने लोकसभा सीटों के मौजूदा राज्य-वार बंटवारे को भी जारी रखने की मांग करते हुए कहा कि लोकसभा में राज्यों के हिसाब से सीटों की मौजूदा संज़्या को अगले 25 सालों तक बनाए रखा जाए। साथ ही, उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने की मांग की।

बिहार की बेटियों को जॉब क्रिएटर बनाने का सपना होगा पूरा: सीएम चौधरी

पटना २७/०८ (संवाददाता): बिहार के मुज़्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक विकसित और समृद्ध बिहार की नींव के तौर पर शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाओं के महत्व पर ज़ोर दिया और लड़कियों को अच्छी शिक्षा, कौशल और बेहतर अवसर देने की जरूरत बताई। 27 अगस्त को, मुज़्यमंत्री ने पटना के मगध महिला कॉलेज में ज+6 साइंस ज़्लॉक और ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी। उन्होंने छात्राओं से उनकी पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी ज़रूरतों, उज़्मीदों और सुझावों पर भी बातचीत की। वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ष्टरू

चौधरी ने कहा कि महिलाओं की तरक्की ही बिहार की तरक्की है। एक विकसित बिहार बनाने के लिए बेटियों और बहनों को अच्छी शिक्षा, आधुनिक सुविधाएँ और मौके देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मगध महिला कॉलेज का नया साइंस ज़्लॉक छात्राओं को विज्ञान की शिक्षा, रिसर्च और करियर के बेहतर मौके देगा। छात्राओं से बातचीत के दौरान, मुज़्यमंत्री ने विकसित भारत और समृद्ध बिहार के सपने को पूरा करने में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की बेटियों को कुशल बनना चाहिए और उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए। उनमें न सिर्फ़ नौकरी पाने वाले, बल्कि नौकरी देने वाले बनने की भी काबिलियत और आत्मविश्वास होना चाहिए। ष्टरू चौधरी ने महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, सज़्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं का भी ज़िक्र किया, जिनमें मुज़्यमंत्री बालिका क्कष्ठ फ़ेलोशिप योजना और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की मदद के लिए बनाई गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शामिल हैं।

उन्होंने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों और समस्याओं का समाधान हाल ही में शुरू किए गए स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल के जरिए किया जाएगा, जहाँ वे अपनी समस्याएँ दर्ज करा सकती हैं और तय समय-सीमा में उनका समाधान पा सकती हैं। मुज़्यमंत्री ने मगध महिला कॉलेज के महिला हॉस्टल का निरीक्षण किया और वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्राओं को कोई परेशानी न हो और पढ़ाई के साथ-साथ खेल-कूद, फिटनेस और अन्य अतिरिक्त गतिविधियों में भी उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।

विविध समाचार

नेपाल बाढ़ में २९० भारतीय लापता, फंसे २०० लोगों को निकालने में जुटा एमईए

नयी दिल्ली २७/०८ (संवाददाता): नेपाल-तिज़्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ के बाद कम से कम 290 भारतीय अब भी लापता हैं, जबकि लगभग 200 अन्य चीन की ओर फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि भारत दोनों देशों के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है, ताकि बचाव अभियान में समन्वय किया जा सके।

इसने कहा कि बचाव अभियान में तेजी आने के साथ भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और संकट से निपटने में उसकी मदद कर रहा है। नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ ने तीन जिलों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ में मरने वालों की संज़्या बढ़कर 359 हो गई।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शीर्ष अधिकारियों तथा काठमांडू और बीजिंग में भारत के राजदूतों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद कहा कि भारत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है। भारत ने बुधवार रात से दो सैन्य परिवहन विमानों के जरिए कुल 47.5 टन आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेजी है और अधिक राहत सामग्री भेजने की प्रक्रिया जारी है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत की तत्काल प्राथमिकता लापता भारतीयों का पता लगाना और उन्हें बचाना तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि नेपाल में लापता भारतीयों में जलविद्युत परियोजनाओं में काम करने वाले लोग और तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों के पर्यटक समूह शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ''290 भारतीय नागरिकों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनमें

वे 73 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जो त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना में काम कर रहे थे।

काठमांडू स्थित हमारा दूतावास इन लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रमुख के संपर्क में है।'' उन्होंने कहा, ''इसके अलावा, तमिलनाडु के 37 और 49 भारतीय नागरिकों के दो अलग-अलग समूह हैं, जो सम्राट और ज़्लाई एवरेस्ट ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे।'' जायसवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय नागरिकों का एक अलग समूह भी था, जो सम्राट ट्रैवल्स की मदद से रसुवा जिले के तिमुरे गया था।

उन्होंने कहा कि वहीं, कुछ अन्य राज्यों के 61 भारतीय नागरिकों का एक और समूह भी था। उन्होंने कहा कि केरल के 33 भारतीय नागरिकों का एक और समूह भी था।

उन्होंने कहा, ''हमने तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों को बचा लिया है... हमें जानकारी मिली है कि मानसरोवर यात्रा पर गए कई भारतीय नागरिक चीन के क्षेत्र में फंसे हुए हैं।'' जायसवाल ने कहा कि तिज़्बत की ओर फंसे लगभग 200 भारतीय नागरिकों ने सुरक्षित निकाले जाने के लिए सहायता मांगी है। उन्होंने कहा कि इनमें से 95 लोग गारचेन में हैं और नेपाल में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि चार लोग जिलॉन्ग शहर में और 13 लोग जुतुलपुक में हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बाढ़ से तबाह हुए क्षेत्रों में स्थिति लगातार बदल रही है और भारत भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है।उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद जयशंकर ने कहा, ''बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि उनका मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, टूर ऑपरेटर और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा, ''हम इस मामले के साथ-साथ राहत प्रयासों को लेकर भी नेपाली पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।'' जयशंकर ने सोशल मीडिया पर कहा, एक दूसरी उड़ान रवाना हुई है, जिसमें नेपाल के लिए 37.5 टन राहत सामग्री, दवाइयां और खाद्य पैकेट भेजे गए हैं। उन्होंने कहा, ''भारत नेपाली अधिकारियों के साथ लगातार और करीबी संपर्क में है। हम जारी राहत प्रयासों को मजबूती से समर्थन देते रहेंगे।'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को नेपाल के अपने समकक्ष बालेंद्र शाह से बात की थी और वहां बाढ़ से जान-माल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त की थी। साथ ही, उन्होंने कहा था कि भारत पड़ोसी देश को हरसंभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा था कि भारत के लोग इस कठिन समय में नेपाल के अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं।

पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बोले नितिन नवीन, ये उनकी अराजकतावादी

नयी दिल्ली २७/०८ (संवाददाता): बुधवार को सज़ारूढ़ भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नेता के शज़्द उनकी अराजक मानसिकता और चरित्र को दर्शाते हैं।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि गांधी की टिप्पणी देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है और उन्होंने उनसे माफी मांगने की मांग की। यह घटना तब हुई जब गांधी ने बुधवार को अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में एक कार्यक्रम में मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विभिन्न मुद्दों पर हमला करते हुए उन्हें गद्दार कहा। गांधी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नबीन ने कहा कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, वह स्पष्ट रूप से उनकी अराजक मानसिकता और चरित्र को दर्शाता है। यह टिप्पणी चुनावों

में अपनी पार्टी की हार से उनकी कुंठा और हताशा को भी दर्शाती है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वे अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। उन्होंने गांधी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। नवीन ने पूछा कि जिस व्यक्ति ने आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगाया, नज़्सलवाद का अंत किया, तिरंगे का सज़्मान बढ़ाया, ऐसे व्यक्ति के लिए आप इस तरह के शज़्दों का प्रयोग करेंगे? उन्होंने मांग की कि राहुल को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल का एक वीडियो साझा किया, जिसमें कांग्रेस नेता कथित तौर पर एक जनसभा में उपस्थित लोगों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्यों को यह बताने के लिए कहते सुनाई दे रहे हैं कि मोदी और शाह 卐गद्दार卐 हैं जिन्होंने देश बेच दिया और संविधान तथा राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला किया।

वीडियो में राहुल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आपको खड़ा होना होगा और लड़ना होगा। जब आरएसएस कार्यकर्ता आपके घरों में आकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में बात करें, तो आपको उन्हें बताना होगा कि उनका संगठन, मोदी और शाह गद्दार हैं। उन्होंने हमारे देश को बेचने की कोशिश की है और हमारे संविधान, अंबेडकर जी और महात्मा गांधी पर हमला किया है। ङ्क पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में भंडारी ने कहा कि गांधी की टिप्पणियां शहरी नज़्सलियों की मानसिकता को दर्शाती हैं और आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 140 करोड़ भारतीयों को गद्दार कहा है। इससे पता चलता है कि उनका नियंत्रण भारत विरोधी ताकतों के हाथ में है। भंडारी ने आगे आरोप लगाया कि गांधी इसलिए नाराज हैं ज़्योंकि मोदी के नेतृत्व में 卐भारत एकजुट है卐 और उन पर भारतीय राज्य को ही निशाना बनाने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले-देश में आने वाला है आर्थिक तूफान

नयी दिल्ली २७/०८ (संवाददाता): लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की राजकोषीय नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि भारत अभूतपूर्व आर्थिक तूफान के कगार पर है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विज़ीय संशोधनों का अंततः पतन होगा और इसका सबसे अधिक बोझ आम नागरिक पर पड़ेगा। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दौरान मीडिया और जनता को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा आर्थिक ढांचे को चुनिंदा अरबपतियों को श्रमिक वर्ग की कीमत पर लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थित रूप से हेरफेर किया गया है। गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जहां बड़े-बड़े कॉरपोरेट जगत के दिग्गज और राजनीतिक नेता अपने महलों में पूरी तरह सुरक्षित

बैठे हैं, वहीं इस आसन्न संकट का असली असर उज़र प्रदेश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए भी आलोचना की कि वे आंतरिक ढांचागत संकटों को दूर करने के बजाय लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं और साथ ही नागरिकों से विदेश यात्राएं कम करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी ने आर्थिक ढांचे में बदलाव किया है और अब एक आर्थिक तूफान आने वाला है। अंबानी के पक्ष में उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया है, वह टिकेगा नहीं; उसका पूरी तरह से ढह जाना तय है। दुख की बात यह है कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाला आर्थिक संकट अडानी, अंबानी और मोदी को प्रभावित नहीं करेगा। बल्कि, यह उज़र प्रदेश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों को प्रभावित करेगा। यह संकट शायद कई वर्षों में न देखी गई तीव्रता के साथ आने वाला है; आगे एक बहुत कठिन दौर है।

भारत-रूस के संबंधों पर किसी देश का वीटो नहीं, पुतिन की यात्रा से नाराज अमेरिका को जयशंकर की दो टूक

नयी दिल्ली २७/०८ (संवाददाता): विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को उन सुझावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया दो दिवसीय भारत यात्रा भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को जटिल बनाएगी। उ

न्होंने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी देश अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ नई दिल्ली के संबंधों को निर्देशित करने की उज़्मीद नहीं कर सकता। एचटी लीडरशिप समिट 2025 में बोलते हुए, विदेश मंत्री ने प्रमुख देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने में भारत की स्वायज़ता का उल्लेख किया और कहा कि किसी भी अन्य देश द्वारा अन्य देशों के साथ नई दिल्ली के संबंधों को निर्देशित करना उचित प्रस्ताव नहीं है।

जयशंकर ने कहा कि मैं असहमत हूँ। सभी जानते हैं कि भारत के दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध हैं। और किसी भी देश के लिए यह अपेक्षा करना कि वह इस बात पर अपनी राय दे कि हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को कैसे विकसित करते हैं, एक उचित प्रस्ताव नहीं है, ज़्योंकि याद रखें, दूसरा भी यही उज़्मीद कर सकता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी देश अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ नई दिल्ली के संबंधों को निर्देशित करने की उज़्मीद नहीं कर सकता। एचटी लीडरशिप समिट 2025 में बोलते हुए, विदेश मंत्री ने प्रमुख देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने में भारत की स्वायज़ता का उल्लेख किया और कहा कि किसी भी अन्य देश द्वारा अन्य देशों के साथ नई दिल्ली के संबंधों को निर्देशित करना उचित प्रस्ताव नहीं है।

विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे बीच बहुपक्षीय संबंध हैं, हमें चयन की स्वतंत्रता है और हम रणनीतिक स्वायज़ता की बात करते हैं, और यह जारी है, तथा मैं कल्पना नहीं कर सकती कि किसी को इसके विपरीत की अपेक्षा करने का कोई कारण ज़्यों होगा। जयशंकर ने देश के किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कड़ी बातचीत करने के नई दिल्ली के रुख को भी दोहराया।उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रज़्प के नेतृत्व वाले नए प्रशासन के बिल्कुल अलग दृष्टिकोण को भी स्वीकार किया, लेकिन विश्वास व्यक्त किया कि एक संतुलित समझौता संभव है। जयशंकर ने कहा कि हर सरकार और हर अमेरिकी राष्ट्रपति का दुनिया से संपर्क करने का अपना तरीका होता है।

मैं आपको यह बता सकता हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप के मामले में, यह उनके पूर्ववर्ती के तरीके से बिल्कुल अलग है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाते हुए भारत के प्रमुख आर्थिक हितों की रक्षा करने में अत्यंत विवेकपूर्ण कदम उठा रही है। आपको बस बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करनी है। हमारा मानना है कि हमारे अपने-अपने व्यापारिक हितों के लिए एक निर्णायक बिंदु हो सकता है, जिस पर कड़ी बातचीत की जाएगी -- ज़्योंकि अंततः मज़दूरों, किसानों, छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग के हित ही मायने रखते हैं। जयशंकर ने कहा कि मैं असहमत हूँ। सभी जानते हैं कि भारत के दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध हैं। और किसी भी देश के लिए यह अपेक्षा करना कि वह इस बात पर अपनी राय दे कि हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को कैसे विकसित करते हैं, एक उचित प्रस्ताव नहीं है, ज़्योंकि याद रखें, दूसरा भी यही उज़्मीद कर सकता है।

विरोध, विरोध, विरोध और समर्थन... कैसे हुआ ये? आलोचक ही बनते जा रहे फैन, अब पीएम मोदी को ढूंढने होंगे नए क्रिटिक

नयी दिल्ली २७/०८ (संवाददाता):महात्मा गांधी ने कहा था कि पहले वे आपको अनदेखा करते हैं फिर वे आप पर हंसते हैं फिर वे आपसे लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। सालों से पीएम मोदी के कट्टर आलोचकों ने उनकी हर नीति की आलोचना कीए उन्हें भला बुरा कहा और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और उनके कट्टर आलोचक उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। पीएम मोदी को नए नफ़रत करने वालों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आइए देखें कि कैसे पीएम मोदी के कट्टर आलोचक उनके सबसे बड़े प्रशंसक बन गए हैं। दिल्ली में एक परिचर्चा के दौरान रूस.यूक्रेन युद्ध और भारत की कूटनीति पर टिप्पणी करते हुए शशि थरूर ने कहा कि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि 2022 में रूस.यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख़

की आलोचना करने पर मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मोदी ने दो हज़्तों के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगाया और दोनों जगह उन्हें स्वीकार किया गया। कभी हर मोर्चे पर पीएम मोदी का विरोध करने वाले उमर अज़्दुल्ला अब उनके शासन के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार कर रहे ह

नीतियों से लेकर सुधारों तकए पूर्व विरोधी मोदी मोदी करने लगे हैं। उमर अज़्दुल्ला ने सार्वजनिक मंच से कहा कि आपने कहा कि आप दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी को खत्म करने पर काम कर रहे हैं और यह वास्तव में आपके काम से साबित होता है। आपने जज़्मू कश्मीर के लोगों से कहा था कि बहुत जल्द चुनाव होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। आपने अपनी बात रखी और 4 महीने के भीतर चुनाव हुए। प्रियंका चतुर्वेदी से एक पॉडकास्ट में उनके फेवरेट लीडर के बारे में पूछा गया था। प्रियंका चतुर्वेदी ने बगैर किसी लाग लपेट के सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे महान नेता तो बताया हीए कुछ देर तक उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़ती रहीं। न्होंने कहा कि पीएम मोदी लोगों से जुड़ने में माहिर हैंए खासकर युवाओं और महिलाओं से। प्रियंका चतुर्वेदी ने माना कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जिज़्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित किया है। बीजेपी की प्रमुख आलोचक रही शरद पवार की बेटी और एनसीपी ;शरद पवारद्ध की नेता सुप्रिया सुले ने हाल ही में भारतीय रेलवे की तारीफ कर दी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में रेलवे द्वारा किए गए कार्य की सराहना की।

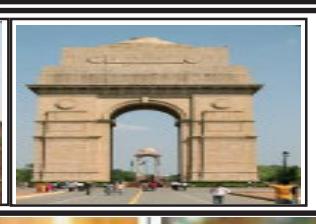

विविध समाचार

सबसे पहले गणेश जी को ही क्यों बांधते हैं राखी?

सनातन परंपरा में श्रीगणेश केवल एक देव नहीं, बल्कि हर शुभ कार्य के निर्विघ्न सपन्न होने की पहली कसौटी हैं। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बाँधती है, तो उस पावन अनुष्ठान का आरंभ देवों के देव प्रथम पूज्य गणेश जी के द्वार से ही होता है।

प्रथम पूज्य का सर्वोच्च स्थान: किसी भी मांगलिक कार्य, पूजा या अनुष्ठान में सबसे पहला अधिकार भगवान गणेश का होता है। भाई को राखी बाँधने की रस्म भी एक पवित्र अनुष्ठान है, इसलिए विघ्नहर्ता से अनुमति और आशीर्वाद स्वरूप पहली राखी उन्हें अर्पित की जाती है।

भाई के लिए अभेद्य सुरक्षा चक्र: गणेश जी का एक नाम 'विघ्नहर्ता' है। उन्हें राखी अर्पित कर बहन वास्तव में अपने भाई के जीवन की हर बाधा, संकट और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की प्रार्थना करती है।

सद्बुद्धि और सफलता का वरदान: गणपति ज्ञान और विवेक के दाता हैं। उन्हें राखी बाँधने से भाई को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा, सद्बुद्धि और हर कार्य क्षेत्र में विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

पारिवारिक मूल्यों की डोर: जब गणेश जी ने माता-पिता (शिव-पार्वती) की परिक्रमा कर पूरे ब्रह्मांड का सुख उन्हीं में पाया, तो उन्होंने यह सिद्ध किया कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। उन्हें राखी बाँधकर भाई-बहन के इस रिश्ते में वही अटूट समर्पण और प्रेम माँगा जाता है।

रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया! राखी बांधने का शुभ समय और सही मुहूर्त

रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार राखी पर यानी 28 अगस्त 2026 के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा और फिर रक्षा बंधन का त्योहार कब बनाएं? श्रावण पूर्णिमा की शुरुआत 27 अगस्त (गुरुवार) की सुबह 9:08 बजे से हो रही है। श्रावण पूर्णिमा का अंत 28 अगस्त (शुक्रवार) की सुबह 9:48 बजे होगा। उदयातिथि के अनुसार, रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा।

ग्रहण का प्रारंभ, अंत और प्रभाव

प्रारंभ अंत: 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण सुबह 6 55 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे समाप्त होगा। प्रभाव: यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। शास्त्रों का स्पष्ट विधान है कि जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल मान्य नहीं होता। इसलिए भारत में इसका कोई दोष या अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राखी बांधने का सबसे शुभ समय:

सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त: सुबह 06:23 से लेकर 09:48 के तक।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर 01:05 तक।
गोधूलि मुहूर्त : शाम 06:57 से लेकर शाम 07:19 बजे तक।
चौघड़िया मुहूर्त:
लाभ: सुबह 07:57 से 09:31 तक।
अमृत: सुबह 09:31 से 11:05 तक।
शुभ: दोपहर 12:40 से 02:14 तक।
चर: शाम 05:22 से 06:57 तक।
लाभ: रात्रि 09:48 से 11:14 तक।
राहुकाल: दिन में 11:05 से दोपहर 12:40 तक। इसलिए अभिजीत मुहूर्त में बांधते वक्त इसका ध्यान रखें। संक्षेप में कहे तो चंद्र ग्रहण का कोई भी छाया-दोष भारत में नहीं लग रहा है। बहनें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर इस पावन पर्व को पूरे उत्साह के साथ मना सकती हैं।

भाई-बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन

श्रावण मह की पूर्णिमा को रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। यदि भाई और बहन एक समान उम्र के हैं तो उनमें प्यार और तकरार चलती रही है परंतु उन्हें एक दूसरे का दोस्त भी बनना चाहिए।

- आपका भाई या आपकी बहन आपके लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दोस्त साबित हो सकते हैं। आज के दौर में लड़की द्वार किसी अन्य से दोस्ती रखना खतरे का खेल भी है।
- भाई या बहन आपके सबसे अच्छे दोस्त तब साबित हो सकते हैं जबकि आप उनके साथ संवाद स्थापित करें और एक दूसरे का ध्यान रखें।
- भाई या बहन के साथ साथ आप अपने सुख-दुःख बांटकर खुश रह सकते हैं।
- भाई ही बहन की मदद करने के लिए हरदम तैयार रहता है और बहन भी भाई की मदद के लिए सदा तत्पर रहती है।
- इस रक्षा बंधन पर भाई के हाथ में बांधे दोस्ती का सूत्र और भाई भी बदन के साथ दोस्ती का नेक दें।
- रक्षाबंधन का दिन ऐसा मौका है, जबकि भाई-बहन गिले-शिकवे भुलाकर आपसी प्यार को बांटते हैं।
- भाई की रक्षा के लिए बहने उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं।
- भाई भी बहन को उपहार देकर उसके सुख-दुःख में साथ देने का वचन देता है।
- इस अनूठे मौके पर अनोखा उपहार देकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं।
- कभी कभार चल सकता है कि आप बाहर के लोगों के साथ भी समय बिताएं पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने तो अपने होते हैं बाकी सब सपने होते हैं। इसीलिए परिवार के सदस्य एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समय दें और उन्हीं के साथ घूमने फिरने जाएं।

सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस पर्व में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा तिथि का होना जरूरी है, और भद्रा वर्जित है। पुराणों में भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन बताया गया है, और किसी भी शुभ कार्य की इसकी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। रक्षा बंधन के दिन सुबह स्नान करके देवता, पितर, और ऋषियों का स्मरण किया जाता है। इसके बाद रक्षा सूत्र (राखी) को गाय के गोबर से लिपे शुद्ध स्थान पर रखकर विधिपूर्वक पूजा की जाती है। फिर रक्षा सूत्र को दाहिने हाथ में बंधवाया जाता है।

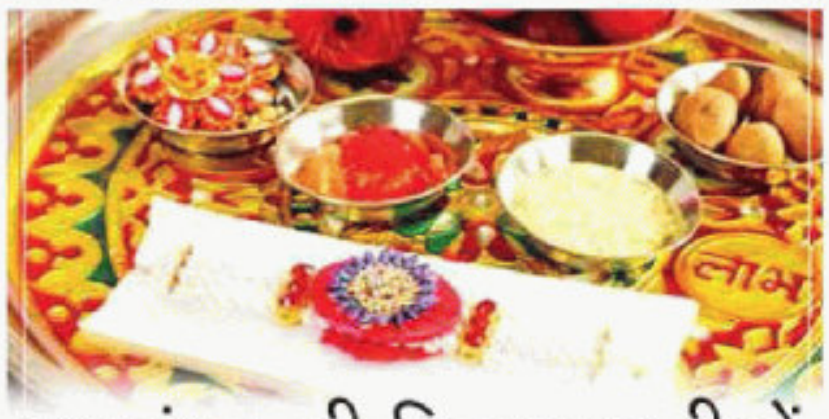

रक्षाबंधन की तिलक थाली में क्या-क्या रखना है जरूरी?

रक्षाबंधन भाई-बहनों के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है जिसमें बहनें प्यार से अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं। साथ ही उन्हें उपहार देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह त्योहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा तो चलिए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

रक्षा बंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है यह एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है, जिसका भारत में बहुत अधिक महत्व है। यह पर्व भाई-बहन के बीच के अटूट प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन शब्द का अर्थ है - सुरक्षा का बंधन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बहनें इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने की कसमें खाते हैं। रक्षाबंधन की थाली में शामिल करें ये चीजें रक्षाबंधन की थाली में रोली, अक्षत, हल्दी, नारियल, राखी, दीपक, मावा से बनी मिठाई या फिर खीर आदि चीजों को शामिल करें। ऐसा कहा जाता है कि इनके बिना पूजा अधूरी होती है। साथ ही इन सभी चीजों का थाली में होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें समृद्धि और शुभता का प्रतीक है, जिसे शामिल करने से भाई के जीवन में सौभाग्य और खुशहाली आती है।

माता-पिता करें ये 10 कार्य, तो बनेगी भाई बहन में अच्छी दोस्ती

- भाई बहन के बीच किसी भी प्रकार का फर्क ना करें।
- दोनों को साथ ही खेलने और शिक्षा प्राप्त करने का मौका दें।
- कोशिश करें के वे साथ में बैठकर ही भोजन करें।
- वो साथ समय बिता सके इसके लिए एक समय तय कर दें।
- वर्ष में एक या दो बार पूरा परिवार सैर सपाटे के लिए बाहर जाएं।
- उन्हे एक दूसरे का खयाल रखना सिखाएं और एक दूसरे की मदद करना सिखाएं।
- उनके भीतर पारिवारिक भावना और टीम भावना का विकास करें।
- जब भी दो एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करें, उनकी प्रशंसा करें।
- एक दूसरे के जन्मदिन पर दोनों को ही कुछ करना सिखाएं।
- रक्षाबंधन के त्योहार को हर वर्ष कुछ स्पेशल करें या स्पेशल बनाएं।

सावन पूर्णिमा के दिन करें ये खास उपाय, मिलेगा लक्ष्मी-नारायण का आशीर्वाद

श्रावण पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय होता है और इस महीने में की गई पूजा का विशेष फल मिलता है।

श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मन शुद्ध होता है। अब ऐसे में सावन पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय है, जिन्हें करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए इस लेख में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं।

दांपत्य जीवन सुखमय के लिए उपाय

अगर आप चाहते हैं कि आपका दांपत्य जीवन खुशहाल रहे, तो सावन पूर्णिमा के दिन हाथी की मूर्ति खरीदकर लाएं और इसे अपने बेडरूम के टेबल पर रखें। इससे दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है।

शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए उपाय

शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए सावन पूर्णिमा के दिन अन्न दान करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विधिवत रूप से करें। ऐसा करने से शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है।

कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए उपाय

कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए सावन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप विशेष रूप से करें और उन्हें पीले मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है।

आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उपाय

अगर आपको हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, तो सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही माता लक्ष्मी के स्तोत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा इस दिन चांदी से संबंधित कोई चीज खरीदें और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है।

सावन पूर्णिमा के दिन इन चीजों के दान से मनोकामनाएं होंगी पूर्ण

सावन पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिव भक्त पूरे विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। पूर्णिमा के दिन यह कृपा और भी बढ़ जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से पापों का नाश होता है। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

सावन पूर्णिमा के दिन करें अन्न दान

सावन पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन अन्न दान करना उत्तम माना गया है। इसलिए सावन पूर्णिमा के दिन अन्न दान जरूर करें।

सावन पूर्णिमा के दिन करें गुड़ दान

सावन पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करने उत्तम माना गया है। इस दिन गुड़ का दान करने से व्यक्ति को कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और अक्षय फल की भी प्राप्ति होती है। सावन पूर्णिमा के दिन करें तिल का दान सावन पूर्णिमा के दिन तिल का दान करने से ग्रहदोष से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही व्यक्ति को कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि तिल का दान करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों को मुक्ति मिलती है। तिल को धन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए, तिल का दान करने से धन में वृद्धि होती है।

सावन पूर्णिमा के दिन करें सफेद चीजों का दान

सावन पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, सफेद चीजों का दान करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों को शांति मिलती है। साथ ही उत्तम परिणाम भी मिलते हैं।

क्या होती है वैदिक राखी?

धार्मिक महत्व और भाई के लिए क्यों हैं शुभ

रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास होता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती। साथ ही, उसकी लंबी आयु की कामना करती है। इसलिए यह त्योहार काफी खास होता है। इस साल की राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि संस्कार, संरक्षण और सद्भाव का सूत्र बना सकती है। इसलिए इस बार आप वैदिक राखी के तौर पर बना सकते है।

क्या होती है वैदिक राखी?

- वैदिक राखी का पहले के समय में काफी इस्तेमाल की जाती थी। दूर्वा याने घास, अक्षत, चंदन, सरसो और केसर को मिलाकर जो राखी बनाई जाती है, उसे ही वैदिक राखी कहते है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कई सारे तत्वों को मिलाकर एक रक्षा सूत्र बनाया जाता है, जो भाई के लिए बेहद खास होता है।
- वैदिक राखी में इस्तेमाल हुई चीजों का अर्थ क्या है
- वैदिक राखी में दूर्वा का इस्तेमाल किया गया है, जो जीवन में स्थिरता, दीर्घायु और विघ्ननाश का कारक होती है।
- अक्षत जिसे अखंड का प्रतीक माना जाता है। इसका इस्तेमाल भी वैदिक राखी में होता है।
- केसर वैदिक राखी की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे अग्नि तत्व कहा जाता है।
- चंदन मन को शांति देता है। साथ ही, विवेक, शुद्ध बुद्धि को बढ़ाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल भी वैदिक राखी में किया जाता है।
- सरसो के दाने शनि दोष से सुरक्षा, दुष्ट दृष्टि से बचाव करता है। इससे वैदिक राखी और खास हो जाती है।

वैदिक राखी को कैसे बांधे?

- एक शुद्ध लाल या पीला धागा लें।
- ऊपर दिए गए तत्वों को श्रद्धा और मंत्र के साथ रक्षा-सूत्र में जोड़ें या स्पर्श कराएं।
- भाई को तिलक लगाकर आरती करें।
- राखी बांधते समय यह रक्षा मंत्र बोलें
- येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥

वैदिक राखी भाई के लिए क्यों हैं शुभ?

इस बार आप वैदिक राखी को बनाकर अपने भाई को पहनाएं। इससे उसकी आयु और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। साथ ही, जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए आप भाई को वैदिक राखी को बांधें।

रक्षाबंधन के लिए कैसी हो राखी

रक्षाबंधन के दिन बहनों को ऐसी राखी का चुनाव करना चाहिए, जो देखने में सुंदर, कच्चे धागे, रेशम आदि की बनी हो. प्लास्टिक से बनी राखी का उपयोग न करें. भूरे और काले रंग की राखी न बांधें. आजकल चांदी और सोने की राखी भी चलन में है, उसे भी बांध सकती है. हालांकि यह सभी के लिए संभव नहीं है.

कलिंग समाचार

संपादकीय

नवीन और प्राचीन के बीच भाजपा

नितिन नबीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नयी दिल्ली में भाजपा मु यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। इससे पहले श्री नबीन को 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। 18 जनवरी को उनका नामांकन हुआ और वे पूर्णकालिक अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए। उनके अध्यक्ष बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें माला पहनाई, फिर करीब एक घंटे के भाषण में कहा, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं कि नितिनजी मेरे बॉस हैं। अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। वहीं बतौर अध्यक्ष नितिन नबीन ने पहले भाषण में कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को मिला स मान है। इन बातों को सुनकर किसी को भी लगेगा कि देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा कितने लोकतांत्रिक मिजाज़ की है। यहां साधारण से कार्यकर्ता को भी शिखर तक पहुंचने का मौका मिलता है। एक राष्ट्रीय दैनिक ने तो शीर्षक ही दे दिया –भाजपा का नवीन युग। अलंकार के हिसाब से शीर्षक काफी उपयुक्त है। लेकिन असलियत क्या है ये नितिन नबीन भी जानते हैं, उनके पूर्ववर्ती जे पी नड्डा भी जानते होंगे और भाजपा के बाकी कार्यकर्ता भी। नितिन नबीन बिहार में पांचवी बार के विधायक हैं, यानी राजनीति में उनकी पकड़ है, इससे कोई इंकार नहीं। लेकिन राजनीति में वे अपने पिता भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा की आकस्मिक मौत के बाद आए। पिता की विरासत संभालनी थी, लिहाजा भाजपा ने परिवारवाद की चिंता किए बिना उन्हें टिकट दी। और फिर लगातार चुनाव जीतकर नितिन नबीन ने अपनी योग्यता साबित की। अब उसी परिवारवाद को भुलाकर ही उन्हें पहले कार्यकारी और फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष भी बनाया गया। क्योंकि वे अमित शाह और नरेन्द्र मोदी की पसंद हैं। जे पी नड्डा भी मोदी–शाह की ही पसंद थे, और बतौर अध्यक्ष उनका कार्यकाल बढ़ा–बढ़ाकर उन्हें शीर्ष पद पर बिठाए रखा गया। लेकिन इसके बाद शायद मोदी–शाह को लगा होगा कि इससे ज्यादा खींचने में पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो शीर्ष पद का मोहरा बदल दिया गया। वैसे भी बिहार चुनाव जीतने के बाद मोदी–शाह को राज्य का धन्यवाद करना था, तो इसका एक तरीका यही लगा होगा। दूसरी बात युवा चेहरे को आगे रखने से रणनीतियों को धार देने में आसानी भी होती है। ध्यान रहे कि छह अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी थी और नितिन नबीन का जन्म इसके भी क़रीब दो महीने बाद 23 मई 1980 को हुआ था। यानी जितनी उम्र पार्टी की है, उतनी ही उसके अध्यक्ष की भी। लेकिन इससे भी उनके नाम के चयन का कोई लेना–देना नहीं है। आज की तारीख में भाजपा में आगे रहने की एकमात्र योग्यता मोदी–शाह की पसंद होना है। जिस कांग्रेस पर भाजपा बार–बार परिवारवाद बढ़ाने का आरोप लगाती है। गांधी परिवार के वर्चस्व की आलोचना करती है, वहां स्थिति बिल्कुल अलग है। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने। उन्हें शशि थरूर ने चुनौती भी दी थी। भाजपा की तरह यहां निर्विरोध नामांकन नहीं हुआ। पार्टी के भीतर अब भी कई कांग्रेस नेता किसी फैसले पर अपनी अलग राय देते हैं, या असहमति व्यक्त करते हैं, इसके बाद भी पार्टी में बने रहते हैं। भाजपा में यह सब कभी नहीं हुआ। पहले अटल–आडवानी के युग ही भाजपा थी, जिसमें जना कृष्णमूर्ति, कुशाभाऊ ठाकरे और बंगारू लक्ष्मण जैसे कमजोर अध्यक्ष बनाए गए। नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेताओं ने भी पार्टी की कमान संभाली, लेकिन उनसे चुनौती मिलते देख उन्हें किनारे भी कर दिया गया। अब नितिन नबीन कब तक हाशिए से दूर रखे जाएंगे, ये देखना होगा। वैसे उन्होंने भाजपा का अध्यक्ष पद तब संभाला है, जब पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है। 240 लोकसभा सीटें, 99 राज्यसभा सीटें, और 21 राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार है। अधिकतर नगरीय निकायों पर भी भाजपा का ही कब्जा है। सत्ता के लिहाज से तो पार्टी काफी मजबूत है, लेकिन क्या संगठन के तौर पर भी यही मजबूती नितिन नबीन कायम रख पाएंगे, ये देखना होगा।

जनतंत्र की खोखल, तानाशाह की जीत!

राजेंद्र शर्मा

चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की अपनी चदरिया जिस तरह से उतार कर रख दी है और जिस तरह आयोग वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के शिविर का हिस्सा बन गया है, उसके बाद तो चुनाव की तारीखों के एलान से पहले और उसके बाद के दौर में, व्यावहारिक मायनों में शायद ही कोई अंतर रह गया है। और चूंकि मोदी–शाह की जोड़ी तो हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है, उसके लिए तो यह विभाजन और भी आभासी है। फिर भी बाकायदा चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर मतदान तक के दौर और उससे पहले के दौर में, एक अवधारणात्मक अंतर तो अब भी बचा ही है।

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने आने वाले विधानसभाई चुनावों के लिए अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है। यह दूसरी बात है कि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों का एलान तक नहीं किया है। अनुमान है कि अप्रैल में होने वाले चुनावों के लिए, फरवरी के दूसरे पखवाड़े में चुनाव आयोग किसी समय चुनाव की तरीखों की घोषणा कर सकता है। यानी यह वह अंतराल है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी को आधिकारिक रूप से सत्ता के चुनावी दुरुपयोग से अपने चुनावी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए खुली छूट मिली रहती है। वैसे याद रखने वाली बात यह भी है कि केंद्र सरकार उर्फ सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार की सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखकर, चुनाव आयोग के चुनाव की तारीखों का एलान करने बाद, विधिवत चुनाव प्रचार का जो दौर शुरू होता है, उसमें भी कौन सा सत्ताधारी पार्टी और उसके स्टार प्रचारकों को, किस तरह की रोक–टोक का सामना करना पड़ता है।

चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की अपनी चदरिया जिस तरह से उतार कर रख दी है और जिस तरह आयोग वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के शिविर का हिस्सा बन गया है, उसके बाद तो चुनाव की तारीखों के एलान से पहले और उसके बाद के दौर में, व्यावहारिक मायनों में शायद ही कोई अंतर रह गया है। और चूंकि मोदी–शाह की जोड़ी तो हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है, उसके लिए तो यह विभाजन और भी आभासी है। फिर भी बाकायदा चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर मतदान तक के दौर और उससे पहले के दौर में, एक अवधारणात्मक अंतर तो अब भी बचा ही है।

लेकिन, हमेशा से ऐसा ही नहीं था। बेशक, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने और आम तौर न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक, राज्य के स्वतंत्र स्तंभों से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं तक पर, कार्यपालिका की ताकत के बल पर, तमाम वैध–अवैध तरीकों से तेजी से कब्जा कर लिया गया है। लेकिन, इससे पहले तक हमारी चुनाव व्यवस्था के विकास की दिशा इससे ठीक उल्टी थी। बेशक, चुनाव प्रणाली पूरी तरह से दोषमुक्त तो शायद कभी भी नहीं थी, फिर भी उसके विकास की दिशा चुनावों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा समावेशी बनाने की ओर थी। यहां तक कि पिछली सदी के आखिरी दशक में तो टीएन शेषन के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाने के लिए मजबूत शुरूआतें भी की थीं, जिनमें आदर्श चुनाव संहिता का लागू किया जाना भी शामिल था। और इसके लिए उन्होंने लड़कर कार्यपालिका से चुनाव आयोग की निष्पक्षता हासिल की थी, जो कि चुनाव प्रक्रिया की तमाम निष्पक्षता की बुनियाद है।

लेकिन, अब चुनाव प्रक्रिया के विकास की उस दिशा को पूरी तरह से ही पलटा जा चुका है। उल्टे चुनाव प्रक्रिया पर पूरी तरह से कार्यपालिका का नियंत्रण स्थापित कराया जा चुका है। और इस उल्टी यात्रा में स्वतंत्रता, निष्पक्षता, जनतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता के आश्वासनों को अधिक से अधिक खोखला करने के लिए, नित नये–नये तजुर्बे किए जा रहे हैं। एसआइआर या मतदाता सूचियों का विशेष सघन पुनरीक्षण, ऐसा ही ताजातरीन एक्सपेरीमेंट है, जिसने चुनाव प्रक्रिया को जनता की राय जानने की प्रक्रिया के बजाए, शासन के मर्जी से मतदाताओं के ही छांटे जाने की प्रक्रिया बनाए जाने का खतरा पैदा कर दिया है।

यह खतरा कितना वास्तविक है, इसका अंदाजा जिन राज्यों में इस समय यह प्रक्रिया चल रही है, वहां इस प्रक्रिया को मतदाताओं की टार्गेटेड छंटनी का हथियार बनाए जाने की हर रोज आ रही खबरों से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से बड़ी सं या में अल्पसं यक और दलित तथा अन्य कमजोर जातियों व महिलाओं के नाम काटे जाने की खबरें आने के साथ–साथ, मुस्लिम बस्तियों में रहने वालों के पतों पर, बड़ी सं या में अनजाने हिंदुओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़े जाने की खबरें आ रही हैं। उधर राजस्थान से एक हिंदू मतदाता सूची अधिकारी का वीडियो संदेश सोशल मीडिया में वाइरल हो रहा है जिसमें यह अधिकारी इसकी धमकी दे रहा है कि अगर उस पर मुसलमानों के नाम काटने और दबाव डाला गया तो, वह आत्महत्या कर लेगा।

और पश्चिम बंगाल में तो, जहां मतदाता सूची के काम में लगे अधिकारियों की चिंताजनक रूप से बड़ी सं या में आत्महत्याओं ने इसे राजनीतिक बहस का मुद्दा ही बना दिया है, भाजपा नेताओं की गाड़ियों में हजारों की सं या में, मतदाताओं के नाम काटे जाने के प्रपत्र पकड़े गए हैं। यह लक्षित तबकों या संभावित रूप से विरोधी मतदाताओं के नाम कटवाने के संगठित खेल की कहानी कहता है।

राजस्थान में भी, पहले चरण में नहीं काटे जा सके, राजनीतिक विरोधी व अल्पसं यक मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए, डेढ़ लाख से ज्यादा परिपत्र मशीनों की मदद से जमा कराए जाने के उदाहरण सामने आये हैं। पाठकों को याद दिला दें कि संगठित तरीके से और औद्योगिक पैमाने पर, वर्तमान मतदाताओं के नाम कटवाने का यह खेल सबसे पहले राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पकड़ा गया था, जिसे भाजपा–विरोधी पार्टियों के हो–हल्ला करने के बावजूद, चुनाव आयोग ने बहुत हद तक अनदेखा ही कर दिया था।

बाद में संभावित रूप से विरोधी वोटों की कटाई के साक्ष्ययुक्त भंडाफोड कर्नाटक के मामले में देश ने देखे। दूसरी ओर, महाराष्ट्र तथा हरियाणा आदि में मु यत: फर्जी मतदाता जोड़े जाने के जरिए, मतदाता सूचियों में धांधली के भंडाफोड़ देश ने देखे।

खैर, सत्ता पक्ष के अश्वमेध के घोड़े पर लौटें, जिसे पांच विधानसभाओं के आने वाले चुनावों में जीत के लिए छोड़ा जा चुका है। जैसाकि आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है, इस घोड़े ने दो प्रकार के बड़े उल्लंघनों से यह अभियान शुरू किया है, लेकिन चुनाव आयोग को इन उल्लंघनों के दिखाई देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहला उल्लंघन सांप्रदायिक डॉग व्हिसलिंग का बड़े पैमाने पर सहारा लिया जाना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने और उनसे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने, प. बंगाल तथा असम के अपने सघन दौरों में, तथाकथित घुसैठियों के मुद्दे को अपने प्रचार के मु य राजनीतिक मुद्दे के तौर पर विशेष जोर देकर उछाला है। जैसाकि हमने अपने पिछले लेख में रेखांकित किया था, मोदी–शाह जब घुसपैठियों की बात करते हैं, तो उनके निशाने पर तमाम मुसलमान होते हैं। संघ परिवार की शब्दावली में घुसपैठिया, मुस्लिम का पर्यायवाची शब्द ही है। उनकी बोली में इन शब्दों की समानार्थकता कितनी गहरी है, इसे इसी सचाई से समझा जा सकता है कि उनकी परिभाषा के अनुसार, सिर्फ मुसलमान को ही घुसपैठिया माना जा सकता है। चाहे दूसरे किसी देश से अवैध रूप से ही आया हो, हिंदू तो %%शरणार्थी%% ही माना जाएगा! नागरिकता संशोधन कानून या सीएए के जरिए मोदी सरकार, इस बंटवारे को कानूनी रूप भी दे चुकी है और एक वैधानिक फर्जीवाड़े के जरिए, बिना संशोधन के ही संविधान के धर्मनिरपेक्ष आधार में यानी नागरिकता की परिभाषा में संशोधन भी कर चुकी है। फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि 2024 के आम चुनाव से अब तक, अति–उपयोग से इस उल्लंघन की कहानी, घिसकर काफी भोंथरी भी हो चुकी है और उसे पूरी तरह से अनदेखा करने के हिसाब से, चुनाव आयोग से लेकर मीडिया तक की खाल ठीक–ठाक मोटी भी हो चुकी है।

इन दौरों में लगातार किया जाता दूसरा बड़ा उल्लंघन, जिसके चुनाव आयोग को नजर ही नहीं आने की बात तो छोड़ ही दें, विपक्ष तक उसे मुद्दा बनाना भूल चुका है, मोदी–शाह की जोड़ी द्वारा सरकारी खजाने और सरकारी योजनाओं का, अपने निजी चुनावी संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। इसे साधा गया है, सरकारी योजनाओं की घोषणाओं को, मतदाताओं पर निजी उपकार में तब्दील करने के जरिए। नरेंद्र मोदी ने जैसे चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले के दो–तीन महीनों के अपने सरकारी कार्यक्रम के नाम पर चुनावी दौरों में, सरकारी योजनाओं के ऐलानों को नया नॉर्मल ही बना दिया है। यह वास्तव में अधिकार संपन्न नागरिकों को, सारी संप्रभुता समेटे शासक की कृपा पर निर्भर, प्रजा बनाकर रखे जाने का ही नया नॉर्मल है। यह वह मुकाम है, जहां न सिर्फ सत्ताधारी वोट के जरिए अपना लंबे समय तक सत्ता में बने रहना सुनिश्चित कर सकता है, यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि जनतंत्र के अर्थ में चुनाव का कोई अर्थ ही नहीं रह जाए है।

अगर जनतंत्र को फासीवादी तानाशाही का खोल भर बनकर रह जाने से बचाना है, तो सत्ताधारियों के साथ मिलीभगत किए बैठा चुनाव आयोग देखे या नहीं देखे, सुने या नहीं सुने, जनतंत्र के एक–एक उल्लंघन का तब तक हिसाब मांगना होगा, जब तक यह लोगों के नागरिक की अपनी पहचान के पुनराविष्कार का महत्वपूर्ण साधन नहीं बन जाता है।

ट्रंप के चंगुल से ग्रीनलैंड को बचाने के लिए कितनी दूर जा सकता है यूरोपीय यूनियन?

नित्य चक्रवर्ती

यूरोप में कुछ और आवाज़ें भी हैं जो ट्रंप के ऐसा करने पर यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती कब्ज़े का रास्ता अपनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, ब्रूसेल्स में यूरोपियन पॉलिसी सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव फेबियन जुलेग ने कहा कि अगर यूरोप एकजुट रहता है, तो वह ट्रंप को दिखा सकता है कि उनकी %जैसे को तैसा% वाली ज़बरदस्ती की कीमत चुकानी पड़ेगी। ग्रीनलैंड के भविष्य पर चर्चा के लिए वॉशिंगटन वार्ता विफल हो गई, जिसमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री व्हाइट हाउस से यह संदेश लेकर घर लौटे कि ग्रीनलैंड सही मायने में अमेरिका का है और ट्रंप इसके अधिग्रहण के समय पर फैसला करेंगे। अमेरिका को यूरोपीय यूनियन (ईयू) या नाटो में यूरोपीय सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। अपने बड़े भाई अमेरिका से ऐसा थप्पड़ खाने के बाद, ईयू नेताओं ने गुरुवार को कुछ धमकी भरे बयान दिए, जिसमें सदस्य देशों के सैनिकों को ग्रीनलैंड के साथ सतर्क और चौकस रहने और डेनिश सैनिकों के नवीनतम अ यास, जिसे ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस कहा जाता है, में सहयोग करने के लिए कहा गया।

भारत की विदेश नीति में बिखराव और दिशाहीनता का दौर यह सब दिखावा है। ट्रंप भी जानते हैं कि ईयू नेता कितनी दूर तक जा सकते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने हमेशा बड़ी–बड़ी बातें की हैं, यह घोषणा करते हुए कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा नहीं कर सकता, तथा डेनमार्क ईयू और नाटो का सदस्य है। अगर अमेरिका कोई आक्रमण करता है तो इस देश की रक्षा की जाएगी। लेकिन फ्रांसीसी अधिकारी पर्दे के पीछे से कोई ऐसा फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो औपचारिक अधिग्रहण को छोड़कर ग्रीनलैंड पर अमेरिका को अतिरिक्त अधिकार दे। द्यह्यश ऋद्धड्डस्र – ललित सुरजन की कलम से – प्रधानमंत्री या ब्रांड ए बेसेडर वेनेजुएला पर अमेरिकी आक्रमण और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकडने के तुरंत बाद, ईयू राष्ट्र इस कार्रवाई के उतने विरोधी नहीं थे, बस उन्हें ट्रंप की कार्रवाई के तरीके पर कुछ आपत्तियां थीं। लेकिन ग्रीनलैंड पर, छह यूरोपीय शक्तियों – फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, पोलैंड और यूके – के ईयू नेताओं ने एक दुर्लभ संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें डेनिश संप्रभुता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की गई और, प्रभावी रूप से, ट्रंप को ग्रीनलैंड से दूर रहने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड अपने लोगों का है– %डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ़ डेनमार्क और ग्रीनलैंड का है।द्यह्यश ऋद्धड्डस्र – प्रधानमंत्री के केरल दौरे से भाजपा को ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा नहीं हुआ ग्रीनलैंड 1979 से एक अर्धस्वायत्त इलाका रहा है, लेकिन डेनमार्क का हिस्सा होने के नाते, इसकी रक्षा नाटो करता है। नाटो के नेता के लीडर के तौर पर, अगर रूस या चीन से कोई खतरा होता है, तो अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा पक्का करने का कुछ अधिकार ज़रूर है। लेकिन सच तो यह है कि पहले के सालों में, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड की संयुक्त रक्षा के लिए शीत युद्ध काल की संधियां लागू थीं। उस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा कर सकता था, लेकिन इसके बजाय, पहले की अमेरिकी सरकारों ने 17 में से 16 मिलिटरी बेस बंद कर दिए, यह सोचकर कि ग्रीनलैंड के आसपास इतने सारे अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले की सरकारों को लगा कि रूस और चीन से कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। ज़्यादा जानें मौसम अपडेट अलर्ट फ़िल्म समीक्षा सेवा मनोरंजक सामग्री सच तो यह है कि यह ताजा कदम आर्कटिक सागर में इस द्वीप की लोकेशन और बड़े प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की संभावना को देखते हुए अमेरिकी साम्राज्य को बढ़ाने की ट्रंप की अपनी कोशिश थी, जिसके लिए रूस और चीन भी मैदान में हैं। रूस और चीन दोनों ने नाटो को किसी भी सुरक्षा खतरे से इनकार किया है और कहा है कि उस ज़ोन में उनकी पेट्रोलिंग समझौते और समुद्री कानूनों के अनुसार हो रही है और ग्रीनलैंड या वहां तैनात नाटो सेनाओं को कोई खतरा नहीं है। ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के ट्रंप के प्रस्तावित कदमों से डेमोक्रेट्स गुस्से में हैं। उन्होंने ट्रंप के इस कदम का विरोध करने के लिए कांग्रेस सदस्यों के बीच एक प्रस्ताव पेश किया है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप दो साल बाद चले जाएंगे, लेकिन नाटो में जो दरारें आई हैं और अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ती खाई ने आपसी संबंधों को प्रभावित किया है, इसे जारी नहीं रहने देना चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल के दिनों में यूरोपीय देशों की ओर से एक डील मेकर के तौर पर ट्रंप से दो बार बात की। ब्रिटिश विदेश सचिव अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात कर रहे हैं, लेकिन राजनयिक सूत्रों का मानना है कि व्हाइट हाउस के अधिकारी भी अनजान हैं। उन्हें ट्रंप की सोच और हर घंटे उसमें होने वाले बदलाव पर निर्भर रहना पड़ता है। यूरोप में कुछ और आवाज़ें भी हैं जो ट्रंप के ऐसा करने पर यूरोपीय देशों द्वारा अमेरिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती कब्ज़े का रास्ता अपनाया जा रहा है। उदाहरण के लिए, ब्रूसेल्स में यूरोपियन पॉलिसी सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव फेबियन जुलेग ने कहा कि अगर यूरोप एकजुट रहता है, तो वह ट्रंप को दिखा सकता है कि उनकी %जैसे को तैसा% वाली ज़बरदस्ती की कीमत चुकानी पड़ेगी। पेरिस के कॉलमनिस्ट अलेक्जेंडर हर्स्ट के लिए, यूरोप के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह अमेरिका के साथ %संबंध तोड़ दे%, जिसमें अमेरिका से अपने यूरोपियन मिलिटरी बेस छोडने के लिए कहना भी शामिल है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा होने के बावजूद, ग्रीनलैंड 9वीं सदी से राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से यूरोप से जुड़ा हुआ है– खासकर दो औपनिवेशिक शक्तियों, नॉर्वे और डेनमार्क से। डेनमार्क ग्रीनलैंड के बजट राजस्व का दो–तिहाई हिस्सा देता है, बाकी मु य रूप से मछली पकडने से आता है। वहां संभावित तेल, गैस और दुर्लभ खनिज भंडार ने खोज करने वाली कंपनियों को आकर्षित किया है।

अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता रहा है और शीत युद्ध के दौरान थुले में एक रडार बेस स्थापित किया था। ग्रीनलैंड के आसपास बर्फ पिघलने से, नए व्यापार मार्ग खुलने की संभावना बढ़ गई है, जिससे आर्कटिक का महत्व बढ़ गया है। ग्रीनलैंड की आबादी लगभग 57,000 है और इसका क्षेत्रफल 21 लाख वर्ग किमी है। ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड के हर नागरिक को एक लाख अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की है ताकि वे अमेरिका के कब्ज़े का समर्थन करें। वह द्वीप को अमीर बनाने के लिए ग्रीनलैंड में बड़े निवेश की बात कर रहे हैं। इस तरह व्यरिक्तगत स्तर पर भी, अमेरिका कब्ज़े के लिए काम कर रहा है। यूरोप के लिए, यह लड़ाई बहुत मुश्किल है। यह जल्द ही साफ हो जाएगा कि महान स यता का दावा करने वाले यूरोपीय देश, अपने बड़े भाई अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड को लेकर चल रही इस लंबी लड़ाई में अपना आत्म–स मान बनाए रख पाते हैं या नहीं।

विविध समाचार

सहकारिता एक भरोसा, टूटने नहीं देंगे : मुकेश अग्निहोत्री

शिमला। नाबार्ड द्वारा आज शिमला में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उप–मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता एक भरोसा है जिसको हम टूटने नहीं दे सकते। सरकार और सहकार मिलकर काम करेंगे और सहकारिता को हम कैसे आगे बढ़ाये इसके बारे में मंथन करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, नई पीढ़ी को सहकारिता से कैसे जोड़ा जा सकता है इस विषय पर भी मंथन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में जब–जब भी सहकारी की बात की जाएगी, तब–तब हिमाचल का नाम हमेशा लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि सहकारी के चौंपियन चाहे कोई भी राज्य बनने की कोशिश करें, लेकिन यह हकीकत है कि सहकारी का अलख हिमाचल प्रदेश ने जगाया है। हिमाचल प्रदेश में पहली सहकारी सोसाइटी बढेड़ा में पंजीकृत हुई थी। उन्होंने बताया की सहकारी का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है, जो लगभग सरकार के बराबर का है जिसका बजट भी सरकार के बजट के लगभग ही है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा हमारे जितने भी सहकारी बैंक है उनका सोसाइटी के प्रति व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम कैसे अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सके। यहाँ पर जो पूंजी है वो लोगों के विश्वास की पूंजी है, लोग अगर सोसाइटी पर पैसा लगाते है तो एक विश्वास पर पैसा लगाते है और किसी भी स्थिति में यह विश्वास हमारा हमेशा कायम रहना चाहिए। हिमाचल ने सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। भुट्टिको की बात करें तो उसके उत्पाद आज देश–विदेश में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री भी कुल्लवी टोपी पहनते हैं और जब प्रधानमंत्री विदेश में राष्ट्र अध्यक्षों को सम्मानित करते हैं तो नाम हिमाचल का होता है। भुट्टिको ब्रांड की विश्वसनीयता कायम हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सहकारिता का शिक्षा के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में ऊना जिला में हिम कैप्स ने सहकारी जगत का पहला लॉ कॉलेज खोला है। उन्होंने बताया कि सहकारी का कोई मालिक नहीं, लेकिन समिति इस संस्था को बहुत सफलतापूर्वक तरीके से चला रही है, जिससे निकले वकील और जज आज सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। इसी संस्था ने नर्सिंग का संस्थान भी खोला है, जिससे निकली नर्स आज देश के कोने–कोने में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि डिजिटल दुनिया में हम प्रवेश कर रहे है और नाबार्ड उसका हमारा साथी है और इनके सहयोग से हमारी सारी सोसाइटी डिजिटल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि धारा 118 के तहत जिस सोसाइटी के पास जमीन नहीं है वहां पर वो प्रोजेक्ट नहीं आ सकते हैं। इसके लिए हमने कानून तैयार कर लिया था, जो विधान सभा में पेश भी हुआ था, जिसमें हमने कहा था कि जिस सोसाइटी के सारे निदेशक हिमाचली है उनको इससे छूट दी जाये ताकि जो मूल रूप से हिमाचली है उनको दिक्कत न आये और उनको अनुमति के लिए इधर–उधर न जाना पड़े, लेकिन वो बिल सेलेक्ट समिति को चला गया है, जिसका बजट सेशन तक कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। उन्होंने बताया कि काँगड़ा की चाय की सोसाइटी, लाहौल की आलू सोसाइटी, कुल्लू की हिम बुनकर सोसाइटी को पुनः सक्रिय करना समय की जरुरत है, जिसके लिए नाबार्ड को सोचना होगा कि इनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। सरकार और सहकार कैसे इन्हे पुनः सक्रिय कर सकते हैं इस पर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के नेटवर्क को आगे बढ़ाने में नाबार्ड प्रदेश सरकार का सहयोग कर रहा है, जिसके तहत लगभग 110 करोड़ रुपए की पूंजी जारी करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त, दूध के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य हुआ है। दूध की समितियां भी बनाई जा रही है जिसके तहत 900 समितियों का गठन किया जा चुका है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत लोग आना चाहते हैं जिसके तहत अगर कोई हिमाचली प्लांट लगाना चाहता है तो उसको 100 वाट तक स्वीकृति दी जा सकती है जिस पर सब्सिडी का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड का सड़कों, ट्रांसपोर्ट, सहकारिता, पानी आदि क्षेत्रों में पूरा सहयोग मिल रहा है जिसके लिए वह उनके आभारी हैं।

मोहाली में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व एडिशनल एडवोकेट की पत्नी का कत्ल, कुर्सी से बंधा मिला नौकर

एस. ए. एस. नगर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी अशोक गोयल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। यह दुखद घटना फेज–5 में उनके घर पर हुई, जहां गोयल अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनका ऑफिस पहली मंजिल पर है। सुबह जब हाउसकीपर काम से घर में घुसी तो उसने अंदर अशोक गोयल की बॉडी देखी और तुरंत पुलिस को बताया। इसी बीच नौकर कुर्सी से बंधा हुआ मिला। सूचना के बाद ैच सिटी दिलप्रीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, घर में लूटपाट हुई और ज्वेलरी और कैश लूट लिए गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं और ब्ब्ज्ट फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि अगर लुटेरों ने बुजुर्ग

महिला की हत्या की तो जवान नौकर को जिंदा क्यों छोड़ दिया? शक के आधार पर पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। हिरासत में लिया गया नौकर नीरज (25) पिछले 9 साल से गोयल परिवार के साथ काम कर रहा था। घटना के समय कृष्ण कुमार गोयल मस्कट में अपनी बेटी के पास गए हुए थे।

ग्रामीण विद्युतीकरण: रोशनी के साथ विकास का उजाला

केन्द्र सरकार हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए एकीकृत योजना वी बी जी राम जी लेकर आई है। इसके पीछे व्यापक नजरिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों का टिकाऊ विकास हो। इसके लिए रोजगार सृजन और बुनियादी ढाँचा विकास पर बल दिया जाएगा। विकास की व्यापक कार्ययोजना को गति प्रदान करेगी विद्युत ऊर्जा जिसे मोदी सरकार ने अपने पिछले दो कार्यकाल में प्रमुखता प्रदान की थी। भारत जहाँ लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है वहाँ ग्राम और ग्रामीण की ऊर्जा संपन्नता ही विकसित भारत के लक्ष्य को परवान चढ़ाएगी। छज़्ीसगढ़ को इस मामले में बढ़त हासिल है। छज़्ीसगढ़ सिर्फ सरप्लस बिजली वाला राज्य नहीं बल्कि यहाँ की बिजली लोगों की समृद्धि का बड़ा कारक है। गौर करने वाली बात यह भी है कि राज्य बनने के पहले तकनीकी रूप से प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा विद्युतीकृत हो चुका था पर उपभोक्ताओं की संज़्या और वितरण गुणवज़ा के लिहाज से स्थिति बहुत निराशाजनक थी। बीते 25 वर्षों को इस लिहाज से अहम माना जा सकता है ज़्योंकि अब गाँव तकनीकी रूप से ही नहीं बल्कि जमीनी तौर पर विद्युतीकृत हैं। वैसे यह जानना रोचक है कि छज़्ीसगढ़ में मध्यभारत प्रांत के दौर में (1 नवंबर 1956 के पूर्व) ग्राम विद्युतीकरण की शुरूआत हो गई थी। मोहला–मानपुर जिले के कुल्हारडोह गाँव को यह सौभाग्य मिला । यहाँ 1953 में बिजली आई, यह अलग बात है कि विद्युतीकरण की परिभाषा तब कुछ और थी। इसके बाद रायपुर जिले के अभनपुर ज़्लॉक के मानिकचौरी गाँव में अगस्त 1956 में मध्यप्रदेश बनने के पहले तथा मध्यप्रदेश बनने के बाद सबसे पहले 31 दिसंबर 1956 में बस्तर जिले के जगदलपुर ज़्लॉक के जीरागाँव में बिजली की दस्तक हुई। यह सिलसिला चल पड़ा एक एक कर सभी जिलों में बिजली पहुँचती चली गई। वर्तमान 33 जिलों में से 06 जिलों के पहले ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष 1970 में हो गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण को लेकर सरकारों ने काम तो शुरू से किए पर प्राथमिकता का क्षेत्र बदलता रहा है। स्वतंत्रता बाद 50 के दशक में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई के साथ ही लघु उद्यम को प्राथमिकता प्रदान की गई। 60 के दशक में अकाल के भयंकर दौर को देखते हुए विद्युतीकरण को सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण पर केंद्रित किया गया। 70 के दशक में सिंचाई पंपों के साथ मूलभूत अधोसंरचनाओं में बिजली उपलज़्धता प्राथमिकता थी। 80 के बाद ग्रामीण आबादी तक बिजली की पहुँच को प्रमुखता दी गई। इधर बीता एक दशक बहुत अहम रहा है जब देश के हर गाँव और हर घर को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया जिसे समय से पूर्व हासिल भी किया गया। असल में बीते 78 वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा बदलती रही। 1947 के बाद लगभग पाँच दशक तक (अज़्टूबर 1997 तक) किसी गाँव के राजस्व क्षेत्र में बिजली का उपयोग किए जाने पर वह गाँव विद्युतीकृत माना गया। अज़्टूबर 1997 के बाद इसमें बदलाव हुआ। किसी गाँव की राजस्व सीमा के अंदर रिहायशी क्षेत्र में बिजली का उपयोग किसी भी कार्य में किया गया (औद्योगिक, व्यावसायिक या घरेलू) तो वह गाँव विद्युतीकृत कहा गया। 17 फरवरी 2004 के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण की परिभाषा को अधिक प्रभावी बनाया गया। गाँव की आबादी वाले क्षेत्र में वितरण लाइन , ट्रांसफार्मर जैसी बुनियादी विद्युत अधोसंरचना स्थापित हो , साथ ही दलित बस्ती में भी ऐसी अधोसंरचना विकसित हो तथा गाँव के कुल घरों में कम से कम 10 प्रतिशत घरों में विद्युत की आपूर्ति की जा रही हो तब वह गाँव विद्युतीकृत माना गया। ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए राष्टीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति ,2006 बनाई गई। सभी घरों में वर्ष 2009 तक बिजली पहुँचाने के साथ ही गुणवज़ापूर्ण और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया। साथ ही न्यूनतम जीवन रेखा खपत 01 यूनिट प्रति घर प्रतिदिन सुनिश्चित किया गया। इस लक्ष्य को पाने के लिए राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के रूप में एकीकृत योजना अप्रैल 2005 में शुरू की गई। इससे ग्रामीण विद्युतीकरण के काम में तेजी आई पर अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू और कृषि दोनों ही श्रेणी के उपभोक्ताओं को गुणवज़ापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवंबर 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। इस योजना ने लक्ष्य आधारित परिणाम दिए हैं और आज ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवज़ापूर्ण विदयुत आपूर्ति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण विद्युतीकरण के दायरे को आगे बढ़ाते हुए हर घर को रोशन करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री हर घर मुज़्त बिजली योजना (सौभाग्य) लागू की गई और 2019 तक हर घर को बिजली से रोशन करने का लक्ष्य रखा गया । ऑफ ग्रिड घरों को सौर ऊर्जा अथवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा माध्यमों से रोशन करना था। इसके सुखद परिणाम आए और आज देश के हर घर में बिजली की पहुँच हो चुकी है। 28 अप्रैल, 2018 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है ज़्योंकि इसी दिन मणिपुर का लेइसांग गांव विद्युतीकृत होने वाला अंतिम गांव बन गया। इस योजना के तहत छज़्ीसगढ़ के ही 7 लाख 31 हजार से अधिक घरों में लोगों ने पहली बार बिजली के बल्ब से रोशनी देखी। 25 वर्ष पहले तत्कालीन परिभाषा अनुसार छज़्ीसगढ़ में 19609 राजस्व गाँवों में से 17108 गाँव विद्युतीकृत थे जो वर्तमान में न केवल शत प्रतिशत विद्युतीकृत हैं अपितु शत–प्रतिशत घरों में बिजली की आपूर्ति हो रही है। आज प्रदेश के 18728 गाँव ग्रिड के माध्यम से तथा 881 गाँव ऑफ ग्रिड पद्धति से बिजली प्राप्त कर रहे हैं। देश में प्रति व्यक्ति औसत विदयुत खपत 1395 यूनिट जबकि छज़्ीसगढ़ में 2211 यूनिट है। इस खपत के बड़े हिस्सेदार ग्रामीण और कृषि उपभोक्ता हैं। खपत का यह आँकड़ा महज दस्तावेजी नहीं । ग्रामीण विद्युतीकरण ने गाँवों के सामाजिक और आर्थिक विकास को व्यापक ढंग से प्रभावित किया है। आज यदि किसान दो से तीन फसल की पैदावार ले रहा है तो इसमें सवा आठ लाख कृषि सिंचाई पंपों का योगदान अहम है। खेती मानव श्रम पर अब भी आधारित है ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो रहे हैं वहीं आर्थिक सबलता से जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की भांति अनेक व्यावसायिक गतिविधियों ने स्थान बनाया है जो अंततः विदयुत की निर्बाध आपूर्ति के कारण फल फूल रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के मजबूत आधार पर आगे बढ़ते हुए ग्रामीण विकास की नई योजना जी राम जी अपने दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करने में निसंदेह सफल होगी।

कृषि क्षेत्र में भारत की कामयाबी क नया मुकाम

साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सज़ा संभालने के एक दशक बाद, भारत का कृषि क्षेत्र साल 2025 तक पूरी तरह से बदल चुका है। कभी कम उत्पादकता, कीमतों में अनिश्चितता और आयात पर निर्भरता से ग्रस्त व्यवस्था, अब रिकॉर्ड उत्पादन, किसानों की सुनिश्चित आय, वैज्ञानिक नवाचार और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता से भरपूर है। दरअसल 2025 को महत्वपूर्ण बनाने के पीछे कोई एक योजना या आंकड़ा नहीं है, बल्कि 11 वर्षों के सुधारों का एक सुसंगत और भविष्य के लिए तैयार कृषि ढांचे में एकीकरण है। 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) ने लक्षित और नतीजों पर फोकस करने वाले कृषि सुधार की दिशा में एक अहम कदम उठाया। केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित और जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह योजना, 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों पर केंद्रित है और इसका मकसद 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। इसके लिए प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ताकि कम उत्पादकता, जल संकट और ऋ्रण की कमी जैसी मुश्किलों का समाधान किया जा सके। 11 मंत्रालयों की 36 कृषि योजनाओं को एकीकृत करके, पीएमडीडीकेवाई ने खंडित कार्यान्वयन को जिला–स्तरीय समन्वय में तज़्दील कर दिया है। एडीपी से प्रेरित यह योजना सिंचाई, भंडारण, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और संस्थागत ऋ्रण को प्राथमिकता देती है, जो मिशन–आधारित कृषि बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत है। वर्ष 2025 में, भारत ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का लक्ष्य 2030–31 तक 350 लाख टन दलहन उत्पादन और 310 लाख हेज़्टेयर में दलहन की खेती करना है। पहली बार, तुअर, उड़द और मसूर उगाने वाले किसानों को बड़े पैमाने पर गुणवज़ापूर्ण बीज वितरण के साथ चार वर्षों के लिए 100त्न न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद का आश्वासन दिया गया है। करीब 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाने वाला यह मिशन, मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करता है, आय को स्थिर करता है और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जो दलहन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी सफलता है। केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित पांच वर्षीय कपास मिशन का मकसद, किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी मदद देकर उत्पादकता बढ़ाना है, खासकर अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की। गुणवज़ापूर्ण कपास की लगातार आपूर्ति करके, यह मिशन भारत के वस्त्र क्षेत्र को मजबूत करता है, जहां 80त्न क्षमता लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा संचालित है। साथ ही यह कृषि को औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रमुख चालक बनाकर, खेतों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के 5एफ दृष्टिकोण को और मज़बूत करता है। इन नीतिगत फैसलों का असर साल 2025 में साफ तौर पर दिखाई दिया। कृषि मंत्रालय द्वारा नवंबर 2025 में जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने 2024–25 में 357.73 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ अब तक का सबसे उच्च स्तर हासिल किया। यह 2015–16 की तुलना में 106 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि दर्शाता है, जब उत्पादन 251.54 मिलियन टन था, जो पिछले दस वर्षों में दर्ज की गई सबसे बड़ी वृद्धि है। 2025 में घोषित प्रमुख उपलज़्धियों में शामिल हैं: चावल का उत्पादन रिकॉर्ड 1,501.84 लाख टन, गेहूं का उत्पादन 1,179.45 लाख टन रहा, जो हाल के इतिहास में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है दालों का उत्पादन 256.83 लाख टन तक पहुंचा तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड 429.89 लाख टन तक पहुंचा 2025 की पहली तिमाही में, भारत के कृषि क्षेत्र ने 3.7त्न की वृद्धि दर्ज की, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कृषि अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। यह उपलज़्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हासिल की गई संरचनात्मक स्थिरता को दर्शाती है। इस बदलाव का एक ज़रुरी स्तंभ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मजबूत करना रहा है। 2014 से पहले, सीमित खरीद के कारण एमएसपी अज़्सर प्रतीकात्मक ही रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, एमएसपी को एक वास्तविक आय संरक्षण व्यवस्था के रूप में संस्थागत रूप दिया गया है। 2025 में, सरकार ने 14 खरीफ फसलों और सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी, जिसमें उत्पादन लागत के 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित करने के सिद्धांत का सज़्ती से पालन किया गया। धान की खरीद (2014–15 से 2024–25) 7,608 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जबकि इससे पिछले दशक में यह 4,590 लाख मीट्रिक टन थी। धान किसानों को एमएसपी भुगतान बढ़कर 14.16 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2014 से पहले भुगतान की गई राशि से तीन गुना से अधिक है। 14 खरीफ फसलों के लिए कुल एमएसपी भुगतान 16.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि पहले यह 4.75 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2025 तक, एमएसपी महज़ एक घोषणा न रहकर, किसानों के लिए एक विश्वसनीय आर्थिक गारंटी बन गया। 2025 में, भारत जीनोम–संपादित चावल की किस्मों को विकसित और जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया.

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, शुक्रवार 28 अगस्त 2026 | पृष्ठ-6

राखी के बहाने ओडिशा में सड़क सुरक्षा का संदेश, जिम्मेदार चालकों को किया गया सम्मानित

भुवनेश्वर २७/०८ (संवाददाता): राखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर ओडिशा परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखा जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में राखी के पारंपरिक संदेश को सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए सुरक्षा के वादे से जोड़ा गया। विभाग ने लोगों से अपील की कि वे सड़क पर चलते समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लें। यह विशेष अभियान राजधानी भुवनेश्वर के एस्प्लेनेड मॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग ने जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए उन वाहन चालकों और राइडर्स को सम्मानित किया, जो लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं और सड़क पर सुरक्षित व्यवहार का उदाहरण पेश कर रहे हैं।

राखी के संदेश को जोड़ा सड़क सुरक्षा से परिवहन विभाग ने इस अभियान के जरिए राखी के भावनात्मक संदेश को सड़क सुरक्षा से जोड़ने की कोशिश की। जिस तरह राखी भाई-बहन के बीच सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है, उसी तरह सड़क पर हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी वाहन चालकों की है। अभियान के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया कि सुरक्षित ड्राइविंग केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, गति सीमा का पालन करना और शराब पीकर वाहन न चलाना सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी कदम हैं। जिमेदार चालकों को मिला सम्मान कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अमिताभ ठाकुर ने उन ड्राइवरों और राइडर्स को सम्मानित किया, जिन्होंने सड़क पर अनुशासन और जिम्मेदारी का परिचय दिया। सम्मान के रूप में उन्हें प्रशंसा-पत्र और उपहार प्रदान किए गए। विभाग का उद्देश्य ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना था, जो यातायात नियमों का पालन कर दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान केवल नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे व्यवहार करने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित करना जरूरी है।लोगों को दिए गए सुरक्षा के संदेश कार्यक्रम के दौरान आम लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर सड़क हादसे तेज रफ़्तार, लापरवाही, हेलमेट न पहनने और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। लोगों से अपील की गई कि वे वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और हमेशा सावधानी बरतें। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया। युवाओं को जागरूक करने पर जोर अभियान में युवाओं को विशेष रूप से जोड़ने का प्रयास किया गया। परिवहन विभाग का मानना है कि युवा वर्ग सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक होगा तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताया गया कि सड़क केवल वाहन चलाने के लिए नहीं, बल्कि सभी के सुरक्षित आवागमन के लिए है। इसलिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क हादसों को रोकना विभाग की प्राथमिकता ओडिशा परिवहन विभाग लगातार सड़क हादसों को कम करने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। विभाग की ओर से समय-समय पर हेलमेट अभियान, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और यातायात नियमों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि केवल चालान काटने से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसके लिए लोगों में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना विकसित करना जरूरी है। सुरक्षा का संकल्प लेने की अपील राखी पूर्णिमा के मौके पर आयोजित इस अभियान के जरिए परिवहन विभाग ने लोगों को एक भावनात्मक संदेश दिया। विभाग ने अपील की कि हर नागरिक सड़क पर चलते समय सुरक्षा को प्राथमिकता दे और अपने परिवार की तरह दूसरों की जिंदगी की भी चिंता करे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि एक छोटी सी सावधानी किसी की जिंदगी बचा सकती है।

आरएसपी के अग्निशमन सेवा विभाग ने कालुंगा पेंट यूनिट में लगी भीषण आग बुझाने में मदद की

राउरकेला २७/०८ (संवाददाता):सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता तथा आम जनता को आपातकालीन सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी को प्रदर्शित करते हुए, सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के अग्निशमन सेवा विभाग ने कालुंगा औद्योगिक विकास केंद्र (आई.डी.सी.) स्थित कावेरी पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग को बुझाने के सामूहिक प्रयास में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। यह घटना 25 अगस्त 2026 को लगभग दोपहर 12 बजे हुई, जब आग ने तेजी से पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। पेंट और थिनर का निर्माण करने वाली इस फैक्ट्री में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों से भरे बड़ी संख्या में ड्रम रखे हुए थे,

जिससे आग और भड़क गई तथा आसपास की औद्योगिक इकाइयों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया।राज्य सरकार के अधिकारियों से सहायता के लिए तत्काल अनुरोध प्राप्त होने पर, आर.एस.पी. अग्निशमन सेवा ने शिफ्ट प्रभारी, श्री एम.एम.बेग के नेतृत्व में 21 अग्निशमन कर्मियों की टीम को घटनास्थल के लिए रवाना किया।

भीषण रासायनिक आग पर काबू पाने के लिए आर.एस.पी. ने 7 अग्निशमन वाहनों का विशेष बेड़ा भेजा। इसमें अत्याधुनिक बहुउद्देशीय अग्निशमन वाहन, 4 फोम अग्निशमन वाहन, 14,000 लीटर क्षमता वाला एक हाई-कैपेसिटी फायर वाटर बॉउजर तथा एक सहायक अग्निशमन वाहन शामिल थे।

ज्वलनशील पेंट सामग्री और थिनर के ड्रमों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए अग्निशमन दल ने 3,500 लीटर अग्निशमन फोम तथा 750 किलोग्राम ड्राई केमिकल फायर फाइटिंग पाउडर का इस्तेमाल किया। घटनास्थल पर अभियान का समन्वय अग्निशमन सेवा के उप प्रबंधक, श्री एस.ए.ठाकोर ने किया।

त्वरित समन्वय और रणनीतिक तरीके से किए गए अग्निशमन अभियान के माध्यम से आग को सफलतापूर्वक सीमित करते हुए नियंत्रित कर बुझा दिया गया, इससे पहले कि वह आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में और फैलती। समय पर की गई इस कार्रवाई ने एक बार फिर राज्य प्रशासन और स्थानीय उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण आपदा-प्रबंधन सहयोगी के रूप में आर.एस.पी. की भूमिका को रेखांकित किया।

सहकारी समितियों के लिए लाभ-मंत्री

गंजाम २७/०८ (संवाददाता): इस्पात खान मंत्री सहकारी समितियों के लिए लाभवाणिज्य, परिवहन और इस्पात खान मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा कि कांग्रेस और बीजद शासन के दौरान राज्य में सहकारी समितियां डूब गई थीं और उनकी सरकार आने के बाद वे नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। सोमवार को गोपालपुर में सहकारी प्रबंध केंद्र के परिसर में गंजाम जिला स्तरीय सहकारी समिति के प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुज्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाले मंत्री जेना ने कहा कि उनकी सरकार समितियों को उनके पूर्व गौरव को वापस लाने के लिए कदम उठा रही है। मुज्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाले राज्य सहकारिताए हथकरघा और औली मंत्री प्रदीप कुमार जलसामंथा ने कहा कि 2024-25 में सहकारी समितियों के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये का ऋण आवंटित किया जाएगा। पिछले साल 830 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस साल 850 करोड़ रुपये का फसल बीमा लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत अनाज खरीद की जिम्मेदारी सहकारी समितियों को सौंपी जा रही है.

जीरा नदी में बढ़ते प्रदूषण से बरगढ़ में चिंता बढ़ी

बरगढ़ २७/०८ (संवाददाता): राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;एस२पीसीबी की रिपोर्ट में जीरा नदी में बढ़ते प्रदूषण को चिन्हित किया गया है, जिससे बरगढ़ के निवासियों में चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट में नदी में गंभीर प्रदूषण को उजागर किया गया हैए जिसके कारण यह उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गई है। रिपोर्ट के अनुसारए सीवेज अपशिष्टों और ठोस अपशिष्ट निपटान के प्रबंधन में बरगढ़ नगर पालिका की विफलता के कारण स्थिति और खराब हो गई है। अपने निरीक्षण के दौरानए एसपीसीबी ने पाया कि कई स्थानों पर अनुपचारित सीवेज को सीधे नदी में बहाया जा रहा था। इसके अतिरिक्तए नदी के किनारों पर असंयोजित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पाया गयाए जिससे पानी की गुणवज़ा और खराब हो गई।

ओडिशा में 18 महीनों में 136 हाथियों की मौत हुई-वन मंत्री

भुवनेश्वर २७/०८ (संवाददाता): वन मंत्री गणेश राम सिंहखुंडिया ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में ओडिशा में अलग-अलग कारणों से 136 जंगली हाथियों की मौत हुई है। ओडिशा विधानसभा में सवालों के लिखित जवाब में वन मंत्री गणेश राम सिंहखुंडिया ने बताया कि अप्रैल 2024 से सितंबर 2025 तक 18 महीनों में बिजली का झटका लगने, शिकार, संक्रामक बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण 136 जंगली हाथियों की मौत हुई। इनमें से 42 हाथियों की मौत बिजली का झटका लगने से, 31 की संक्रामक बीमारियों से और 4 की ट्रेन दुर्घटनाओं से होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा, 31 हाथियों की मौत स्वाभाविक रूप से हुई बताई गई है। इसके बाद, 4 हाथियों के मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण मारे जाने और 4 हाथियों के शिकारियों द्वारा मारे जाने की खबर है।

हालांकि, इस सूची में शामिल लगभग 20 हाथियों की मौत के कारणों की जांच चल रही है। इस स्थिति में, ओडिशा सरकार ने कहा है कि हाथियों की मौत के लिए जिम्मेदार लगभग 92 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके मामलों की अदालतों में जांच चल रही है।

धर्मशाला में झड़प के बाद राजनीतिक बयानबाजी

भुवनेश्वर २७/०८ (संवाददाता): धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक झड़प से तनाव बढ़ गया है, रविवार को हुई हिंसा के लिए दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व विधायक प्रणब बलबंतराय के नेतृत्व में क्षुब्ध कार्यकर्ताओं ने ष्ठत कैंप ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया और धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू की गिरफ़्तारी की मांग की।

यह विरोध प्रदर्शन रविवार को धर्मसाला में एक फार्महाउस पर दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हुआ है।

आरोप है कि झड़प तब शुरू हुई जब विधायक साहू के समर्थकों ने बीजद कार्यकर्ताओं, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, पर हमला किया, जो बलबंतराय के फार्महाउस पर पार्टी की मीटिंग कर रहे थे। बीजद ने 100 से ज़्यादा साहू समर्थकों के नाम का एक नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक महिला के साथ गाली-गलौज और बदसलूकी की। बलबंतराय और उनके समर्थक रात भर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमलावरों के खिलाफ सज्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बलबंतराय ने कहा, हमें जिला पुलिस पर भरोसा नहीं है। जब तक आरोपियों को गिरज्तार नहीं किया जाता, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।

कैश फ्लो को मजबूत करने के लिए सीधे आर्डर पूरे करने को प्राथमिकता देता है आरएसपी

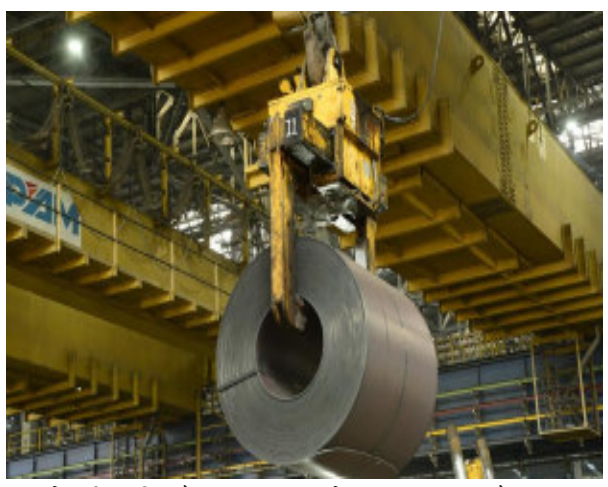

राउरकेला २७/०८ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) ने समय पर बिक्री प्राप्ति सुनिश्चित करने, कार्यशील पूंजी की दक्षता में सुधार करने और नकद प्रवाह को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष आदेश पूर्ति पर विशेष ध्यान बनाए रखा है।जुलाई 2026 के दौरान आर.एस.पी. ने 3,64,649 टन विक्रय योग्य इस्पात की डिस्पैच की। इसमें से 3,00,911 टन इस्पात ग्राहकों के आदेशों के विरुद्ध सीधे डिस्पैच किया गया, जबकि 63,738 टन स्टॉकयार्ड के माध्यम से भेजा गया। इस प्रकार, माह के दौरान कुल डिस्पैच में प्रत्यक्ष आदेश पूर्ति की हिस्सेदारी लगभग 82.5 प्रतिशत रही। संयंत्र द्वारा प्रत्यक्ष ऑर्डर पूर्ति पर ध्यान देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तैयार उत्पादों को पुष्ट ग्राहक आदेशों के आधार पर डिस्पैच किया जाए। इससे उत्पादों की बिक्री से प्राप्ति में तेजी आएगी तथा स्टॉकयार्ड में उत्पादों की आवाजाही पर निर्भरता कम होगी। इस दृष्टिकोण से इन्वेंट्री प्रबंधन में सुधार, बेहतर नकदी प्रवाह तथा संगठन के लिए अधिक विज़ीय लचीलापन सुनिश्चित करने में योगदान मिलने की उमीद है।

अप्रैल से जुलाई 2026 की अवधि के दौरान आर.एस.पी. ने कुल 13,28,999 टन विक्रय योग्य इस्पात डिस्पैच किया। इसमें से 11,28,691 टन प्रत्यक्ष आदेश पूर्ति के तहत डिस्पैच किया गया, जो इस अवधि के कुल डिस्पैच का लगभग 84.9 प्रतिशत है। शेष 2,00,308 टन इस्पात स्टॉकयार्ड के माध्यम से डिस्पैच किया गया। आर.एस.पी. के विशिष्ट उत्पादों, जिनमें पी.ई.टी. श्रेणी के उत्पाद जैसे सी.आर.एन.ओ. और पाइप शामिल हैं, में प्रत्यक्ष आदेश पूर्ति का स्तर लगातार अधिक रहा और यह 90.4 प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं, गैर-पीईटी उत्पादों के लिए यह आंकड़ा 81.4 प्रतिशत रहा। यह प्रदर्शन ग्राहकों की आवश्यकताओं और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन एवं डिस्पैच को व्यवस्थित करने के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।प्रत्यक्ष आदेश पूर्ति पर निरंतर जोर आर.एस.पी. की ग्राहक-केंद्रित परिचालन व्यवस्था, कार्यशील पूंजी के कुशल उपयोग और बेहतर विज़ीय प्रदर्शन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

ग्राहक आदेशों और उत्पाद डिस्पैच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके संयंत्र अधिक उज़रदायी, कुशल और विज़ीय रूप से टिकाऊ बिक्री एवं वितरण प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF DELHI

विज्ञापन सं. R&P/322/2026 **दिनांक: 31.07.2026**

दिल्ली विश्वविद्यालय के **रसायन विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, आनुवंशिकी, भूविज्ञान, हिन्दी, भाषा विज्ञान, क्रियात्मक अनुसंधान, दर्शनशास्त्र और प्राणी विज्ञान** विभागों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के अकादमिक वेतन स्तर-14 में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित आवेदन पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.du.ac.in** पर जाएं और "Work with DU" शीर्षक के अंतर्गत "Jobs and Opportunities" पर क्लिक करें।

किसी भी प्रकार का परिशिष्ट/संशोधन केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

CBC 21231/11/0015/2627 **रजिस्ट्रार**